

प्रेषक,

शिव विभूति रंजन,  
अनुसचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

2. मुख्य विकास अधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल,  
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : 04 नवम्बर, 2015  
विषय : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण सम्बन्धी मुख्यमंत्री कार्यालय के शासनादेश संख्या-100/XXXV-4/15 दिनांक 02 अक्टूबर, 2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.10.2015 एवं 16.10.2015 को राजस्व ग्राम-डबरा तथा राजस्व ग्राम-मंजगांव, तहसील-चौबट्टाखाल में भ्रमण/रात्रि विश्राम कर, सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराते हुए वर्तमान योजनाओं से उन्हें प्राप्त लाभ एवं उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गयी।

2. उक्त भ्रमण में यह ज्ञात हुआ कि ग्राम-डबरा तथा ग्राम-मंजगांव, ग्राम पंचायत-मंजगांव (चौबट्टा), विकासखण्ड-पोखड़ा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में राज्य वित्त/13वें वित्त आयोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा), I.W.D.B योजना के अन्तर्गत कार्य कराये गये हैं। ग्रामीणों को इन योजनाओं की जानकारी है। उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही विविध योजनाओं यथा-विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांग पेंशन, दीन दयाल आवास योजना तथा इन्दिरा आवास योजना इत्यादि की ग्रामीणों को जानकारी है तथा इससे वे पात्रतानुसार लाभान्वित भी पाये गये। उक्त दोनों गांव में बिजली, पानी, सी0सी0 मार्ग, खडंजा मार्ग की सुविधा है। ग्रामीणों के लिए प्राथमिक विद्यालय, इण्टरमीडिएट कॉलेज तथा महाविद्यालय की सुविधा समीपस्थ मुख्य स्थान (पैदल पहाड़ी मार्ग से दूरी लगभग 03 कि0मी0 तथा सड़क के द्वारा लगभग 08 कि0मी0 (किन्तु इस के लिये कोई पब्लिक ट्रॉसपोर्ट नहीं है)) चौबट्टाखाल में है। पात्रतानुसार ग्रामवासी खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं।

3. वर्तमान में उक्त दोनों ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं की क्षेत्रवार स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

क्र० सं०	बिन्दु	वर्तमान प्रास्थिति	समस्या/माँग	अभ्युक्ति एवं सुझाव
1.	सड़क संयोजकता	लोक निर्माण विभाग से ग्राम-डबरा के लिये स्वीकृत सड़क अभी आधी-अधूरी ही बनी है। यह सड़क ग्राम-नौल्यू तक पहुंच पायी है। वर्तमान में मात्र रोड़ कटिंग हुई पायी गयी तथा डामर रोड़ नहीं थी।	ग्रामीणों द्वारा प्रबल मांग की गयी है, कि राज्य गठन के उपरान्त आज तक भी इस रोड़ के न बन पाने के कारण आवागमन की समस्या बनी हुई है। आकस्मिक स्थिति में चिकित्सालय तक पहुंचना	सड़क का निर्माण शीघ्र किया जाना होगा, ताकि ग्रामीणों को सुविधा हो सके। यह सड़क पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई बतायी गयी। इस वित्तीय वर्ष में इस सड़क के



			सम्भव नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा इसे शीघ्र बनाये जाने की मांग की गयी है।	निर्माण कार्य को किया जाना अपरिहार्य है।
2.	प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय	गांव में कोई प्रथमिक विद्यालय नहीं है। गांववासियों के लिये एक विद्यालय था, जिसमें न्यूनतम 05 बच्चे उपलब्ध न होने के कारण वह बन्द हो गया है। ग्रामीणों के लिये दूसरा प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक तथा महाविद्यालय की सुविधा मुख्य मार्ग पर स्थान-चौबट्टाखाल में है।	चौबट्टाखाल प्राथमिक विद्यालय जो समीपस्थ मुख्य स्थान (पैदल पहाड़ी मार्ग से दूरी लगभग 03 कि०मी० तथा सड़क के द्वारा लगभग 08 कि०मी० (किन्तु इस के लिये कोई पब्लिक ट्रॉसपोर्ट नहीं है)) में निर्मित है, जिसके मात्र 02 कक्षाओं में ही पठन-पाठन चल रहा है। शेष कक्षा तहसील भवन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। यद्यपि तहसील भवन के लिये पृथक से भूमि चन्हित है तथा इस हेतु धनराशि की व्यवस्था भी हुई है, किन्तु निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। चौबट्टाखाल इण्टर कॉलेज भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसका पुर्ननिर्माण अति आवश्यक है। विद्यालय में मूल-भूत सुविधाओं यथा-लैब का सामान, फर्नीचर, खेल सामग्री आदि का अभाव है। चौबट्टाखाल महाविद्यालय में भी मूलभूत सुविधाओं की कमी पायी गयी है, जैसे-कॉलेज के नव-निर्मित भवन का कार्य आधा-अधूरा है, निर्मित भवन हैण्डओवर नहीं हुआ है, जीव विज्ञान/भौतिक विज्ञान/वनस्पति विज्ञान की लैब नहीं है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक की तैनाती गत 03 वर्षों से नहीं हुई है।	ग्रामीणों/क्षेत्रवासियों/शिक्षकों द्वारा इसे सुधारे जाने की मांग की गयी है, जो कि व्यवहारिक एवं अपरिहार्य है।
3.	स्वास्थ्य सुविधायें	(1) A.N.M की सुविधा मुख्य मार्ग पर स्थान-चौबट्टाखाल में सृजित नहीं है। A.N.M सेंटर वर्तमान में ग्राम-सौण्डल में किराये के भवन पर चल रहा है। (2) ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा गांव से लगभग 15-18 कि०मी० दूर स्थान-नौगांवखाल में मिल रही है। (3) ग्रामीणों को बड़ी चिकित्सा हेतु गांव से स्थान-सतपुली अथवा पौड़ी या कोटद्वार आना पड़ता है। तहसील अथवा ब्लॉक पर कोई राजकीय चिकित्सालय नहीं है।	ग्रामीणों की मांग है कि A.N.M की सुविधा मुख्य मार्ग पर स्थान-चौबट्टाखाल में होनी चाहिए।	A.N.M, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की सुविधा मुख्य मार्ग पर स्थान-चौबट्टाखाल में न होने से ग्रामीणों को दूर अलग जाकर यह सुविधा मिल पाती है। यहां आने हेतु कोई नियमित वाहन (पब्लिक ट्रॉसपोर्ट) नहीं है। ग्रामीणों का चौबट्टाखाल प्रतिदिन लगभग आना ही होता है, यदि यह मुख्य मार्ग पर स्थान-चौबट्टाखाल में होता तो ग्रामवासी/क्षेत्रवासी बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकते थे।
4.	पेयजल सुविधा	गांव में पेयजल सुविधा सुचारु पायी गयी।	-	-
5.	विद्युत आपूर्ति	गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारु पायी गयी।	-	-
6.	जन खाद्य आपूर्ति प्रणाली	गांव में जन खाद्य आपूर्ति प्रणाली सुचारु पायी गयी।	-	-



7.	आंगनबाड़ी केन्द्र	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम डबरा में 11 परिवार निवासरत हैं। यहां पर कोई आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं पाया गया है।	ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम-डबरा में एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र होना चाहिये।	मिनिकानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता है।
8.	कृषि एवं औद्योगिक निवेश आपूर्ति केन्द्र	कृषि एवं उद्योग की स्थिति अत्यन्त खराब है। जंगली जानवरों यथा-बन्दर, सूअर (PIG) आदि के कारण खेती, बागवानी नहीं हो पा रही है। बांस का उत्पादन भारी मात्रा में है, किन्तु बांस को बाजार उपलब्ध न होने के कारण इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उद्यान विभाग द्वारा कोई शिविर ग्रामीणों की जानकारी हेतु नहीं लगाया गया है।	जंगली जानवरों पर नियन्त्रण किया जाए।	(1) जंगली जानवरों पर नियन्त्रण का उपाय किया जाए। (2) बांस के कय की व्यवस्था की जाए। (3) उद्यान विभाग द्वारा पौली हाउस, फल संरक्षण, फल कय केन्द्र की जानकारी हेतु प्रत्येक माह में 01 दिन गांव में शिविर लगाया जाए।
9.	निजी/सार्वजनिक शौचालय	गांव में निजी शौचालय निर्मित पाये गये।	—	—
10.	समाज कल्याण योजना का लाभ	गांव के अधिकांश वृद्ध/विधवा/विकलांग/परित्यक्ताओं को पेंशन लाभ प्राप्त हो रहा है। कतिपय व्यक्ति बचे हैं, जिन्हें लाभ दिलाये जाने हेतु कार्यवाही ग्राम प्रधान स्तर से की जा रही है।	—	—
11.	सिंचाई/लघु सिंचाई	गांव में छोटी व बड़ी गूलों का निर्माण हुआ है तथा उसमें जल प्रवाह भी पर्याप्त है।	—	—
12.	कानून व्यवस्था	पटवारी के पंजिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कोई राजस्व वाद लम्बित नहीं है।	—	—

**सुझाव :-** गांव भ्रमण एवं जन सम्पर्क से यह ज्ञात हुआ कि गांव की प्रमुख समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार है। गांव में आबादी अत्यन्त कम है, जिसमें अधिकांश वृद्ध/महिला/विकलांग/विधवा है। युवा पीढ़ी का लगभग अभाव है। गांव में अथवा उसके 08 कि०मी० की परिधि में समुचित शिक्षा/चिकित्सा/रोजगार की व्यवस्था नहीं है। कहीं स्कूल हैं, तो शिक्षक नहीं और कहीं शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं। अत्यन्त कम बच्चों के कारण स्कूल भी बन्द करना पड़ा। जंगली जानवरों का आतंक है। ऐसी स्थिति में ऐसा महसूस हुआ कि क्षेत्र के जूनियर/सीनीयर विद्यालयों को बन्द करके ब्लॉक/तहसील स्तर पर बेहतर चिकित्सा व शिक्षा की व्यवस्था विकसित की जाए। ब्लॉक/तहसील स्तर पर 'आवासीय स्कूल' (कक्षा 01 से लेकर परा-स्नातक तक) खोले जायें, जिसमें विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के भी आवास की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार तहसील/ब्लॉक स्तर पर एक बड़ा चिकित्सालय खोला जाए। युवा पीढ़ी तथा महिलाओं की सहकारिता व्यवस्था विकसित कर उन्हें कृषि/बागवानी/फूलों की खेती/मशरूम उत्पादन/पशुपालन का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम उद्यान/पशुपालन विभाग के शिविरों के माध्यम से कराया जाए। राशन की दुकानों को छोटे कय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए, जो किसानों/ग्रामीणों के उत्पाद सरकारी दर/न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे तथा बाजार को उपलब्ध करायें। इन कुछ प्रयासों से पहाड़ों से पलायन के साथ-साथ पहाड़ पर चिकित्सकों तथा शिक्षकों के जाने की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

भवदीय,



(शिव विभूति रंजन)

अनुसचिव



720

संख्या- /VI-2/2015-62(20)15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(शिव विभूति रंजन)

अनुसचिव